

Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22240-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या.- 1499/2026

इजहारुल हक एवं 7 अन्य

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :-शहीद सलाम, फरहान अहमद खान, मोहम्मद काशीफ रफी

रमिष अहमद बैग,शहीद सलाम,स्वधा कुमारी,विभा यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :-शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में, अधिवक्ता श्री नृपेंद्र मिश्रा ने प्रतिवादी संख्या-4 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है।
2. प्रतिवादी संख्या-4 भी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित है, जिसे उप-निरीक्षक वीरेंद्र गोविंद राव, थाना ललिया, जिला बलरामपुर द्वारा लाया गया है।
3. व्यक्तिगत उपस्थिति के मामलों की सूची को पुनरीक्षित किया गया है। पुनरीक्षित पुकार के बावजूद याचिकाकर्ताओं की ओर से इस याचिका पर बल देने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।
4. तात्कालिक याचिका दिनांक 15.01.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो वाद अपराध संख्या 0002/2026 के रूप में पंजीकृत है, अंतर्गत मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धाराएँ 4 एवं 3, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएँ 4 एवं 3 तथा भारतीय

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 351(3), 115(2), 85, थाना ललिया, जनपद बलरामपुर, को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई है।

5. इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2026 के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने यह संकेत दिया था कि यदि मामले को मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया जाता है, तो पक्षों के बीच समझौते की पूरी संभावना है, इसलिए इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपनी सद्भावना दर्शाने के लिए 20,000/- रुपये की राशि जमा करने की अपेक्षा की थी और उक्त राशि जमा करने की शर्त पर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

6. दिनांक 23.03.2026 की कार्यालय आख्याओं के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने न तो उपरोक्त राशि जमा की है और न ही विरोधी पक्षकार संख्या-4 को सूचना जारी करने हेतु कोई कदम ही उठाए हैं।

7. अतः, यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष न केवल असत्य कथन दिया गया है, बल्कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्षों के बीच विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से 20,000/- रुपये की राशि का भुगतान करने के संबंध में व्यक्त की गई सद्भावी भावना का भी पालन नहीं किया गया है। यह स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।

8. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दलीप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य : (2010) 2 SCC 114** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना उपयुक्त होगा, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन वादकारियों की कड़ी निंदा की है जो अपने लाभ के लिए न्याय प्रणाली का उपयोग करते हैं और इस प्रकार न्याय की धाराओं को प्रदूषित करने का प्रयास करते हैं।

9. सुविधा के लिए, **दलीप सिंह (उपरोक्त)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"पिछले 40 वर्षों में, वादकारियों का एक नया पंथ/वर्ग उभर कर आया है। इस वर्ग से संबंधित लोगों के मन में सत्य के प्रति कोई सम्मान नहीं है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेशर्मी से झूठ और अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। वादकारियों के इस नए वर्ग द्वारा उत्पन्न चुनौती का सामना करने के लिए, न्यायालयों ने समय-समय पर नए नियम विकसित किए हैं और अब यह पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि जो वादकारी न्याय की धारा को प्रदूषित करने का

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

प्रयास करता है या जो न्याय के शुद्ध रूप को कलंकित हाथों से छूता है, वह किसी भी अनुतोष का चाहे वह अंतरिम हो या अंतिम हकदार नहीं है।"

10. उपरोक्त निर्णय पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पांडुरंग विठ्ठल केवने बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड व अन्य : 2024 INSC 1051** के मामले में पुनः विचार किया गया है।

11. इसी प्रकार, इस न्यायालय ने **दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 9143/2025 आशीष कुमार व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** के मामले में, जहाँ समान परिस्थितियों में एक वादकारी ने इस न्यायालय का रुख किया था और यह विधिवत दर्शाया था कि वह इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होकर मामले को सुलझाने का इच्छुक है, तथा अपनी सद्भावी भावना दिखाने के लिए उसे एक निश्चित राशि जमा करने की अपेक्षा की गई थी, फिर भी वह न तो उक्त राशि जमा करने में और न ही इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के समक्ष उपस्थित होने में सफल रहा; अतः इस न्यायालय ने निर्णय और आदेश दिनांक 24.11.2025 के माध्यम से उक्त याचिका को 25,000/- रुपये के अनुकरणीय लागत के साथ खारिज कर दिया था, जिसे निर्धारित समय के भीतर भुगतान न करने की स्थिति में, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाना था।

12. सुविधा के लिए, **आशीष कुमार (उपरोक्त)** के मामले में प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"3. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कथन दिया गया था कि यदि मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र को संदर्भित किया जाता है, तो पक्षों के बीच विवाद के सुलझने की पूरी संभावना है। उपरोक्त पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या-4 को सूचना जारी किया था और यह भी अपेक्षा की थी कि याचिकाकर्ता संख्या-1 दस दिन की अवधि के भीतर इस न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि जमा करेगा।

4. दिनांक 18.11.2025 और 21.11.2025 की कार्यालय आख्याओं के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि (क) 25,000/- रुपये की राशि जमा नहीं की गई है और (ख) प्रतिवादी संख्या-4 को सूचना जारी करने हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। यहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता भी आज उपस्थित नहीं हैं।

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

5. इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, इस न्यायालय के समक्ष मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने हेतु कथन देने का एकमात्र कारण न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश देने के लिए राजी करना था। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष 25,000/- रुपये की राशि जमा न करने और प्रतिवादी संख्या-4 को सूचना जारी करने के लिए कदम न उठाने का यह आचरण स्पष्ट रूप से न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को दर्शाता है।

6. उपरोक्त पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका याचिकाकर्ताओं पर 25,000/- रुपये के अनुकरणीय लागत के साथ खारिज की जाती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह लागत राशि चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस न्यायालय के विधिक सहायता प्रकोष्ठ में जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर, उक्त राशि याचिकाकर्ताओं से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

7. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।”

13. पुनः, इस न्यायालय ने दांडिक प्रकीर्ण वाद संख्या 8971/2025 डॉ. नितिन त्रिपाठी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में, समान परिस्थितियों में न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर विचार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"9. जबकि याचिकाकर्तागण इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2025 को व्यक्त किए गए अपने कथनों से पूर्णतः मुकर गए हैं, क्योंकि न तो ₹40,000/- का मांग पत्र तैयार किया गया है और न ही याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई निर्देश प्रदान किए गए हैं, अतः यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रारम्भ में विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारित करने के अपने आशय को प्रदर्शित कर तथा तत्पश्चात उसी से पूर्णतः मुकरकर, जबकि उन्हीं आशयों के आधार पर उनके पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किया गया था, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है।

10. उपरोक्त पर विचार करते हुए, न्यायालय का यह मत है कि यह रिट याचिका अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किए जाने योग्य है।

11. तदनुसार, उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका 40,000/- रुपये के लागत के साथ खारिज की जाती है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह हर्जाना राशि एक माह के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप-समिति, लखनऊ में जमा की जाएगी, ऐसा न करने पर, उक्त लागत राशि याचिकाकर्ताओं से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।"

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

14. उपरोक्त विवेचना को ध्यान में रखते हुए तथा व्यक्तिगत उपस्थिति के मामलों की सूची को पुनरीक्षित किए जाने के बावजूद याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति और 20,000/- रुपये की राशि जमा न किए जाने के कारण, इस न्यायालय के पास इस रिट याचिका को खारिज करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः यह याचिका 20,000/- रुपये के अनुकरणीय लागत के साथ **खारिज** की जाती है, जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय विधिक सेवा उप-समिति, लखनऊ में जमा किया जाएगा। उपरोक्त राशि जमा न करने की स्थिति में, उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

15. हमारे द्वारा 20,000/- रुपये की लागत लगाने का कारण यह है कि यह वही राशि थी जिसे याचिकाकर्ताओं ने अपनी सद्भावना दर्शाने के लिए जमा करने की इच्छा व्यक्त की थी और चूंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई सद्भावी भावना नहीं पाई गई है, इसलिए न्यायालय का यह मत है कि उक्त राशि को अनुकरणीय लागत के रूप में लगाया जाना चाहिए और इस राशि से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा।

16. इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के वरिष्ठ निबंधक को उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

मार्च 30, 2026

केकेवी/

अस्वीकरण:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”